[The Deputy Chairman.]

following amendment be made in the Finance Bill, 1964, as passed by the Lok Sabha, namely:—

'That at page 65, lines 26-27, the words 'and which is such a company as is referred to in section 108 of the Income-tax Act with a total income exceeding Rs. 25,000' be deleted.' "

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the First Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The First Schedule was added to the Bill.

The Second and the Third Schedules were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI T. T. KRISHNAMACHARI: I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we go on to the Appropriation Bill.

THE APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1964—*contd.*

श्री जगत नारायण (पंजाब) : उपसभापति महोदय, इस सदन के मेम्बरों को Report of the Committee on Prevention of Corruption या सन्तानम् रिपोर्ट मिली है। मैं उसमें से एक पैरा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । वह पैरा २१६ है :—

"It was represented to us that corruption has increased to such an extent that people have started losing faith in the integrity of public administration. We heard from all sides that corruption has in recent years, spread even to those levels of administration from which it was conspicuously absent in the past. We wish we could confidently and without reservation assert that at the political level, Ministers, Legislators, party officials were free from this malady. The general impressions are unfair and exaggerated. But the very fact that such impressions are there causes damage to the social fabric. That such impressions should have come into existence in so short a time after the people of this country had given themselves a Constitution of their own is all the more distressing if it is remembered that the struggle for freedom in India was fought on a particularly high moral plane and was led by Mahatma Gandhi who personified integrity. The people of India rightly expected that, when the governance of the country passed into the hands of the disciples of the Father of the Nation who were in their own individual capacities known for high characters and ability, Governments in India, at the Centre and the States, would set up and achieve a standard of integrity, second to none in the world, both in the political and administrative aspects. It has to be frankly admitted that this hope has not been realised in full measure."

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) in the chair]

यह मैंने रिपोर्ट में से पढ़ करके आपके सामने रखा है ।

अब मैं आपकी खिदमत में यह कहना चाहता हूं कि सेंटर ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ़ एक दास कमिशन यहां पर अप्वाइन्ट किया । अगर हमारे फाइनेंस, मिनिस्टर साहब वहां तशरीफ़ ले जांय और दास कमिशन की कार्यवाही जा करके देखें तो वे हैरान होंगे कि वहां जिस करप्शन के लिये सारा यह दास कमिशन बैठाया गया है, उसी करप्शन को जो हमारे मुख्य मंत्री हैं, वे आगे ले जा रहे हैं । आप कहेंगे कि वह कैसे । तो वहां पर जो उनका वकील है

उसका सारा खर्चा पंजाब सरकार की तरफ से हो रहा है इसलिये कि पंजाब के मुख्य मंत्री को बचाया जाय कि उसने करप्शन नहीं की है । और जो खर्चा सरकारी वकील ले रहे हैं उसको सुन कर आप हेरान होंगे । एक मिनट के लिये सरकारी वकील को ८ रु० मिल रहे हैं । एक मिनट के लिये वह जो तकरीर करते हैं या अफेडैविट पढ़ते हैं या और चीज़ पढ़ते हैं तो उसके लिये ८ रु० मिल रहा है और यह सारा खर्चा पंजाब सरकार कर रही है । आप बताईये कि एक मुख्य मंत्री के खिलाफ करप्शन का चार्ज हो, प्रेसिडैंट आफ इंडिया को मेमोरियल दिया जाय और उसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया एक दास कमिशन बैठाये—जो जज है वह कोई तनख्वाह नहीं ले रहे हों, कोई पैसा नहीं ले रहे हों, बाकी सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार से हो रहा हो—एक तरफ यह हो मगर दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि मुख्य मंत्री को बचाने के लिये सारी पंजाब सरकार लगी हुई है, लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है और एक एक मिनट के लिये सरकारी वकील को, मि० सेठी को, जो उनकी तरफ से पेश हो रहे हैं, ८ रु० दिया जा रहा है ।

योजना मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : उनकी फीस क्या है ?

श्री जगत नारायण : फीस क्या है, एक मिनट का ८ रु०, जरब करके एक घंटे का आप समझ लीजिये, एक घंटे की फीस ५०० रु० हो गई ।

श्री बी० आर० भगत : उनका कोई कांट्रैक्ट होगा ।

श्री प्रकाश नारयन सप्रू (उत्तर प्रदेश) : इस तरीके से तो फीस नहीं होती है कि एक मिनट के हिसाब से हो। घंटे भर के हिसाब से लेते होंगे या किसी और हिसाब से लेते होंगे ।

श्री जगत नारायण : एक दिन के लिये १५०० रु० की फीस उन्हें मिलती है और वहां १० बजे तक सारी कार्यवाही होती है, उस सब हिसाब से यह बनता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE): Is it according to the contract?

श्री जगत नारायण : कांट्रैक्ट का तो मुझे पता नहीं है, यह पता है कि दास कमिशन के सामने यह कहा गया था कि वकील साहब को एक मिनट के लिये ८ रू० मिलता है और उसको सेठी साहब ने कांट्रैडिक्ट नहीं किया तो जो कि सरदार कैरों की तरफ से पेश हो रहे हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRAN SATHE): They want to know what is the contract and how you arrive at the figure that he is getting Rs. 8 a minute.

श्री जगत नारायण : वह तो मैंने बताया । कांट्रैक्टस का तो मुझे पता नहीं कि गवर्नमेंट के साथ उन्होंने क्या किया है लेकिन मुझे इतना पता है . . . .

श्री बी० आर० भगत : आपने कहा कि १५०० रू० रोज का है, वह ज्यादा नहीं है ।

श्री जगत नारायण : मेरे कहने का मतलब यह था कि करप्शन चल रहा है, एक चीफ मिनिस्टर पर करप्शन का चार्ज है और उसके लिये दास-कमिशन बैठा हुआ है लेकिन उस मुख्य मंत्री को बचाने के लिये पंजाब सरकार का लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है—मेरा प्वाइंट यह है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था ।

अब मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं । डिफेंस के लिये बहुत कुछ कहा जाता है, इसके लिये रुपया भी बहुत मांगा गया है मगर डिफेंस के लिये हमारे पंजाब में क्या हो रहा है ? वहां हलवाड़ा का हवाई अड्डा केन्द्रीय सरकार की तरफ से बन रहा है । मैडम, आप सुनकर के हैरान होंगी कि इसी केन्द्रीय सरकार ने फैसला किया कि किसी फर्म को १० लाख से ज्यादा का कांट्रैक्ट नहीं देना है क्योंकि उनका यह ख्याल था कि वह

[श्री जगत नारायण]

ठेकेदारी का काम नहीं कर सकते हैं मगर चूंकि वह पंजाब के मुख्य मंत्री के बेटे हैं वहां पर उनको कांट्रैक्ट दिया गया है—चाहे वह बेनामी है या उनके नाम पर है मगर उनको ६१ लाख का अब ठेका दे दिया गया है बजाय १० लाख के और फिर वहां क्या हो रहा है। वहां यह हो रहा है कि अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भेस बदल कर हलवाड़ा के हवाई अड्डे पर तशरीफ ले जायें तो देख कर के हैरान होंगे कि पंजाब गवर्नमेंट के जो सरकारी मुलाजिम हैं वह वहां काम कर रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट का जो सरकारी मसाला है, सीमेंट वह तमाम चीज हलवाड़ा के हवाई अड्डे पर लग रही हैं और जो रुपया है वह हमारे मुख्य मंत्री के बेटों को मिल रहा है। तो जब करप्शन की इंक्वायरी हो रही है तब इस तरह से फिर भी करप्शन जारी है, इस ढंग पर जारी है और केन्द्रीय सरकार की आंखों में भी धूल डाली जा रही है। कोई देखने वाला नहीं है। मैं अपने वजीर सहाब से कहूंगा कि वह भेस बदल कर जांय, अपना दौरा करें मगर भेस बदल कर जांयें और देखें कि वहां पर किस तरह से करप्शन चल रहा है और कैसे सरकारी ठेके दिये हुए हैं।

सिर्फ यही नहीं कहा जाय कि मैं पंजाब के मुताल्लिक ही कह रहा हूं इसलिये मैं आपकी बसातत से अपनी वजारत की खिदमत में और इस हाउस के मेम्बरान की खिदमत में कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी चाहते यह थे कि हिन्दुस्तान का डिवीजन नहीं हो मगर डिवीजन हुआ, हमारे नेताओं ने डिवीजन माना, मगर इसके बावजूद जितना बड़ा हिन्दुस्तान महात्मा गांधी हमें दे कर गये थे आज उतना बड़ा हिन्दुस्तान आपके पास नही है। बड़े दुःख की बात है कि जो हमारी फारेन पालिसी है वह सारी ही फेल हुई है और आज हालत क्या है? आज हिन्दुस्तान की हालत यह है कि जो मुल्क कभी हिन्दुस्तान के हिस्से थे, जो छोटे मुल्क हिन्दुस्तान को अपना बड़ा भाई कहते थे वे तमाम मुल्क आज हिन्दुस्तान के जानी दुश्मन बने हुए हैं और आज हिन्दुस्तान चारों तरफ से उन मुल्कों से घिर गया है जहां कि अब हिन्दुस्तानियों का रहना भी मुश्किल हो गया है। मैडम, आप कहेंगी कि शायद यह यों ही कह रहा है लेकिन देखिये कि हिन्दुस्तान को १९४७ में आजादी मिली और चीन को आजादी मिली १ अक्तूबर, १९४९ को, १९४७ में तिब्बत के साथ जो हमारा मुआहिदा था वह अंग्रेजी सरकार का था और वही मुआहिदा हमारी सरकार को मिला : मैं आप के सामने वह एक पैरा पढ़ना चाहता हूं।

"India attained freedom and the first independent Government took over from the British Government in India.

The new Government had inherited certain extraterritorial rights in Tibet. The Indian Trade Agents settled in personal conference with the Tibetan authorities disputes between the British subjects and the local inhabitants and, where there was a difference of view, the law of the country to which the defendant belonged prevailed, with the officers of the defendant's nationality presiding at the trial. All questions regarding rights arising between British nationals were subject to the jurisdiction of the British authorities. British subjects committing any crime were tried by the Trade Agents and punished according to the laws in India."

ये तमाम बातें तिब्बत में थीं लेकिन आज क्या हालत है वहां पर? आज वहां एक हिन्दुस्तानी नजर नहीं आयेगा। हालत यह है कि जिस चीन के मुताल्लिक यह कहा जाता था कि चीन हमारा दोस्त है, चीन के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात हैं उसी चीन ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को सन् १९५० में लिखा, १९४९ ई० में

उन्होंने आजादी हासिल की और १९५० ई० में उन्होंने लिखा :—

"The Government of China criticised the Government of India 'as having been affected by foreign influences hostile to China in Tibet'."

इमैजिन करिये कि जिस चीन की मदद के लिये हिन्दुस्तान ने इतनी आवाज उठाई उसी चीन ने १९५० ई० में हिन्दुस्तान के खिलाफ वावेला खड़ा कर दिया कि हिन्दुस्तान दूसरे मुल्कों से इमदाद ले रहा है। आज हालत क्या है? चीन का प्रचार हमारे खिलाफ है और चीन का सारा बार्डर हिन्दुस्तान के साथ मिला हुआ है, तिब्बत जो बफर स्टेट था वह खत्म हो गया है और जितने राइट्स हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद मिले वे खत्म हो गये हैं। आज तिब्बत में हिन्दुस्तान के आदमियों का नामोनिशान भी नजर नहीं आयेगा। उसके बाद बर्मा को देख लीजिये वहां लाखों हिन्दुस्तान के आदमी रहते थे, हिन्दुस्तान और बर्मा कभी एक स्टेट हुआ करते थे, वहां हिन्दुस्तान की हुकुमत होती थी, मगर आज वहां की हालत यह है कि हिन्दुस्तानियों को वहां से भाग कर आना पड़ रहा है। पिछले दिनों यह खबर छपी, मैडेम, आप सुन कर हैरान होंगी, वजीर साहब सुन कर हैरान होंगे, मगर यह खबर छपी कि वहां से एक बहन आ रही थी, उसके नाक में एक सोने की नथ पड़ी हुई थी, तो एयरपोर्ट पर वहां नथ काटी गई और इस ढंग से काटी गई कि बहन की नाक को नुकसान पहुंचे और वह बहन कलकत्ता तक आई तब तक उससे खून बहता रहा और उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। आज हिन्दुस्तान के लोग एक मुंदरी क्या, एक छल्ला क्या कुछ भी बर्मा से नहीं ला सकते हैं, सारा उनका बिजनेस नैशनलाइज कर दिया गया है। हालत यह है।

(Time bell rings.)

पांच मिनट की आप और इजाजत दे दें तो मैं अपनी बात कह दूं।

बर्मा को छोड़िये, लंका को देखिये। कितना छोटा लंका का देश है। वहां की हालत देख लीजिये। वहां एक लाख नहीं, २ लाख नहीं बल्कि ४ लाख या ५ लाख हिन्दुस्तानी ऐसे हैं जिन की कोई नेशनैलिटी नहीं है, न उन्हें हिन्दुस्तान के नैशनल कह सकते हैं और न उन्हें लंका के नेशनल कह सकते हैं, यों वह पैदा लंका में ही हुए हैं। वे वहीं पैदा हुए, उन्होंने हिन्दुस्तान को कभी दर्शन नहीं किये मगर आज उनको लंका का नेशनल नहीं कहा जाता है। हमारी सरकार अभी तक चुप बैठी है। और बर्मा में भी पिछले ६ महीनों से हमारा सफीर नहीं जा सका है। इतनी बड़ी सरकार हमारी जो है वह कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने बैंक नेशनलाइज कर दिए, उन्होंने सारे ट्रेड को नेशनलाइज कर दिया, वहां से लोगों को भागना पड़ा है मगर पिछले ६ महीनों से वहां हमारा सफीर नहीं है। हिन्दुस्तान की इतनी बड़ी सरकार और एक सफीर वहां काम नहीं कर सकता है। यह हैरानी की बात है।

मैं आपकी खिदमत में कह रहा था कि चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, हमारा जबर्दस्त झगड़ा चल रहा है। आप को पता ही है कि अयूब ने यहां तक कहा था कि अमेरिका से जो हमें अस्लिहा मिला है यह मत समझिये कि हम उसको रूई की गांठों में रखे रहेंगे, जब मौका होगा हम हिन्दुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान खिलाफ, चीन खिलाफ, लंका खिलाफ, बर्मा खिलाफ और नेपाल के मुतल्लिक हमारी पोजीशन यह है कि वहां भी हिन्दुस्तानी लोग नहीं रह सकते हैं, इतना उनका हाल खराब है कि वहां से उनको निकलना पड़ता है। आज हमारी यह हालत है कि कोई भी पड़ोसी देश हमारा दोस्त नहीं है, वे हमारी जान के लेवा हैं।

[श्री जगत नारायण]

यह हमारी फारेन पालिसी है जिस पर हमें कभी नाज होता था कि इतना बड़ा मुल्क महात्मा गांधी आजाद करके दे गए। (*Time bell rings.*) तो मैं सिर्फ आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितना रुपया आप डिफेंस के लिये ले रहे हैं इस का सोरियला और सही तौर पर खर्च नहीं कर रहे हैं।

SHRI N. SRI RAMA REDDY (Mysore): Madam, I rise to give my whole hearted support to this Appropriation Bill as it has been discussed in this House. As I went through these various appropriations, I found one very astounding figure, rather a figure which has depressed me very much indeed. Out of a total sum of Rs. 10,400 crores of the appropriations, a sum as big as Rs. 250,89,49,000 is appropriated for the purchase of foodgrains. Madam, I really admit that food is a very necessary thing and it has got to be provided for. But at what cost to the economy this is being done is a matter which requires very serious consideration.

India is a very ancient agricultural country. Nearly 70 per cent of the people are living on agriculture. Agriculture is the premier industry of the country and if through agriculture we have not been able to make this country self-sufficient in food and other agricultural raw materials required for the country the state of the economy as being run in this country can better be imagined than described. Rupees two hundred and fifty crores is a very astounding figure and in an agricultural country where 70 per cent of the people are agriculturists. And it is the biggest industry, and the position is like this. It has been so for quite a long time now. And in this respect it is worth while considering what the state of affairs about the importation of foodgrains has been. In 1955-56, the total import of foodgrains was of the order of 393 thousand tons. Of course, even prior to that period we have been importing, but I would like to make a start with the year 1955-56. Even prior to that period, our effort had been that we should become self-sufficient in agriculture, that agriculture should be made to produce all the wealth that was needed in this country through the various Plans. But if we examine the importation of foodgrains into this country at least from 1955-56, we will know towards what end we have been drifting, towards what end our economy has been drifting, towards what end our agriculture has been drifting. This is very pertinent in this respect and therefore I would like to quote. In the next year, in 1956-57, the figure shot up to 2125 thousand tons of foodgrains. These are all said to be normally good years of agriculture production. That is how it is described in this country. In spite of that, in spite of this normalcy and fair harvest, in 1957-58 the position was that we imported 3633 thousand tons of foodgrains. In the subsequent year, in 1958-59, it was 3424 thousand tons; the figure is almost the same. In 1959-60, it went up to 3762 thousand tons. But in 1960-61, the year of the best harvest in the last decade, the position was that we imported 5023 thousand tons. I do not know how to answer this riddle and if the Finance Minister kindly enlightens this House, we shall be very grateful. I do not have the figures for the years 1961-62 and 1962-63 which are said to be very bad agricultural production years. What is the cause? Is it due to the fact that we have not been able to set apart enough money for agricultural production in the country? Could it be explained in that way?

A close analysis of the figures of outlay for agricultural production both by the Centre as well as the States reveals another astounding feature. During the First Plan, the annual outlay on agriculture works out to Rs. 41·16 crores. This is the outlay on agriculture under the First Plan. The percentage of increase in agricultural production on account of

this outlay during the First Plan was 2:8. During the Second Plan, the outlay was increased to Rs. 54:29 crores, and there was an increase of 32 per cent. over the five year period and the increase in agricultural production is reflected in the various figures that I have quoted. An increase of 4 per cent has been effected during the Second Five Year Plan. The outlay in the Third Five Year Plan has been stepped up enormously. The total outlay for the five years in the Third Five Year Plan is Rs. 1,281 crores on account of agriculture.

SHRI KHANDUBHAI K. DESAI (Gujarat): What about the Second Plan?

SHRI N. SRI RAMA REDDY: It is 54·29 crores annually; for five years it works out to Rs. 271·45 crores. The stepping up of the outlay during the Third Five Year Plan has been so outstanding that it has risen to Rs. 256 crores, out of which during the first year of the Third Plan period we have been able to spend only Rs. 176 crores, And what is the result? The increase in agricultural production was only 1·2 per cent. over the last year's production of the Second Five Year Plan. This is the state of affairs in the first year of the Third Five Year Plan. That is why the outlay has increased to Rs. 222 crores, that is nearly 291 per cent. or nearly 300 per cent. more. What is the result? The result is that in the second year of the Third Five Year Plan the agricultural production is 3·2 per cent. For the Third Five Year Plan we do not have the figures as yet but the figures are not very much encouraging indeed. So what is happening to our outlay? Why is that the outlays have not reflected themselves in the agricultural production in the country? What is this snag? Greater and greater appropriations are being asked for by the Ministry of Finance, 200 or 300 per cent. more. But if the increased outlay is explained away by saying that weather was not all right, therefore the crops had failed and all that sort of thing, then outlays have no meaning. If we have no means of getting over some of these natural disadvantages, then outlays have no meaning. There is not much meaning in our increased outlay if we cannot get over these things. I would like to know if there is any way of remedying this situation. For instance, the agricultural production programmes, as adumbrated by the Planning Commission, are exceedingly good each one of them is exceedingly good. But what is happening to the translation of these agricultural production programmes, scientific programmes as they are called, on the field, I ask? Three years of our Third Five Year Plan have been dismal failures with regard to the agricultural production in this country. That means to say that we must go on increasing the import of foodgrains.

Not only this, if we examine the price position with regard to agricultural materials, say, cereals for the last year, from the latest figures given in the reports issued by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, it will be seen that apart from wheat, which has been imported in this country, the increase in prices has been as high as 20 per cent within the last one year. Therefore, all these go to show that our production programmes have miserably failed in spite of the fact that greater and greater amounts have been spent on agriculture. Therefore, Madam, naturally we have a right to ask—though I do not know whom to ask. The Planning Commission do not share the responsibility. The Finance Ministry do not share the responsibility—the reasons for the rising prices. Price-rise in the agricultural commodities is a matter that has got to be explained. The responsibility for this has got to be borne by some Ministry. I would like to know if the Finance Ministry takes the responsibility or not, or whosever it is, the Parliament has a right to put the

[Shri N. Sri Rama Reddy.]

question to the Government and elicit a proper answer for these things from the Government.

Therefore, Madam, the fact remains that agriculture in this country has failed and has been failing and some way has got to be found. If we examine the productivity figures for the crops including rice or wheat or any foodgrain, or cotton or tobacco or potato, there is a dismal failure. I do not want to bore the House.

SHRI P. N. SAPRU: What about soil erosion?

SHRI N. SRI RAMA REDDY: I admit soil erosion is there. But we are spending considerable amount for preventing soil erosion, for reclamation, for bunding, for ever so many things, for artificial manures, for everything, on irrigation and power projects. We are spending crores and crores on all these things. With regard to expenditure there is nothing to complain about. But when it reflects the production, there is dismal failure that you find.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): The hon. Member himself being an expert agriculturist, I think it will help the House if he gave the remedies.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Thank you very much for the compliment. All the same this may not be the proper time for me to go into the details of agricultural production. On some other occasion, if I have the time, I would like to dilate upon those things before the House. But presently I want only to diagnose the disease With regard to the remedies, let us put our heads together, find out the cause for failures in agriculture and find out the remedy. So long as we do not make much headway in agriculture production our backwardness will continue. Our backwardness will continue if we depend upon the American wheat for feeding the millions in this country and we cannot be said to be secure in our freedom. Therefore, it is of fundamental necessity for this country to feel completely free without having to depend upon foreign countries.

SHRI AKBAR ALI KHAN: There we are all agreed.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Let us go into the question and implement our programmes.

Here I may point out, Madam, that our productivity is the least per acre in any field. We are said to be possessing one-fourth of the cattle population of the world but the productivity of milk, which has been described as Amrita from centuries past and which is the most essential food for the human being, is the lowest in the world. The yield of milk per animal here is as low as 224 litres as against 4,000 or 5,000 litres in some of the Western countries. Our wool production per sheep is the lowest in the world. Our egg production per poultry is the lowest in the world.

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh): What about human production?

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Yes, that is probably the highest. It has also been referred to by the hon. Finance Minister when he was replying. There is nothing wanting in that respect.

SHRI AKBAR ALI KHAN: In that also the quality is very poor.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: May be. (*Time bell rings*). I would like to have only five minutes. I may be given chance tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE): Please wind up now.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Therefore, these are some of the matters which require serious consideration of this Parliament, of this honourable

House and the Government. I do not want to take much of your time but these are the facts that have got to be very carefully examined by the Government and remedies found. For remedies I do not put the responsibility completely on the Government. This House is also responsible to find out remedies. And the sooner we do it the better would it be.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 28th April, 1964.

GMGIPND—RS—205 RS—2-7-64—554